benefit and upliftment of fishermen in the country;

(b) if so, the details thereof alongwith achievements of each such centrally sponsored scheme during the Seventh Plan;

(c) the details of scheme included in Eighth Plan for the uplift of fishermen along with financial out-lays and state wise coverage of beneficiaries in general and for Maharashtra State in particular; and

(d) what steps are proposed for modernisation/upgadation of traditional fishing for better returns to fishermen during the Eighth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The schemes and achievements during the 7th Plan are given below:

Scheme	Achievement
Motorisation of Traditional Craft	4,776 craft motorised and central subsidy of Rs. 167.83 lakh released for the purpose.
Introduction of Beach Landing Craft	202 Beach Landing Craft introduced and Rs. 111.08 lakh released as central assistance as subsidy.
Group Accident Insurance for Active Fishermen	About 8.5 lakh fishermen per annum insured and central assistance of Rs. 139.46 lakh released as share of premium for the plan period.
Development of Model Fishermen Villages	18 villages sanctioned and Rs. 265.78 lakh released as central subsidy for the purpose.

(c) and (d) Schemes included in the 8th Plan are as below:

Scheme	Outlay for 8th Plan
Motorisation of Traditional Craft	1000
Introduction of Plywood/FRP Craft	200
Re-imbursement of Excise Duty on HSD Oil by mechanised vessels below 20 m length	5000
Community Managed Artificial Reefs and Mariculture	500
Enforcement of Marine Fishing Regulations Act by States	3000
Group Accident Insurance	200
Establishment of Model Villages	2000
Savings-cum-Relief	2000

No state-wise allocation has been done. Sanction of funds to states is made, as and when proposals are received from the states.

किसानों के लिये लाभकारी मूल्य

2823. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज के लिये लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये क्या प्रयास किये गये है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो वे लक्ष्य क्या हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन): (क) किसानों को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में फसलों के उत्पादन की लागत का आकलन करने की प्रणाली में संशोधन किया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू है। संशोधित परिकल्पनाएं हैं—(1) सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर या वास्तविक मजदूरी दर पर, जो उच्चतर हो, मजदूरी का मूल्यांकन, (2) कुल लागत के 10 प्रतिशत की लागत की एक मद के रूप में प्रबंधकीय-निवेश के रूप में मूल्यांकन और (3) आदानों के मूल्य में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि होने पर बुवाई के मौसम से पहले घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का समायोजन।

(ख) और (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे

में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, आदि के विचारों के आधार पर किया जाता है।

उड़ीसा में भूख के कारण मौतें

2824. **श्री अनन्त राम जायसवाल:** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1992 में उड़ीसा में भूख से आठ यक्तियों की मृत्यु हुई थी और उस क्षेत्र के निवासी आम की गुठलियां और पत्ते खाने को मजबूर हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या भूखमरी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है; यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भूख से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है; यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन): (क) उड़ीसा सरकार ने मौके पर की गई जांच रिपोर्ट में बताया है कि कोरापुट जिले के डोलडोला गांव में 8 लोगों की मृत्यु, आम की विषाक्त गिरी खाने से हुई।

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) मुफ्त भोजन

(2) एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत पोषाहार कार्यक्रम

(3) वृद्धावस्था पेंशन

(4) रोजगारोन्मूलक कार्य

(ग) राज्य सरकार ने शोक संतप्त परिवारों को 32,000/ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें एक एक मकान भी दिलाया जाएगा।

Sale of Cultivable Land to Real Estate Business

2825. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleaded to state the steps Government propose to take to tackle the increasing sale of cultivable land to real estate business creating thereby problems for crop production for the increasing population?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Conversion of agricultural land into residential sites is taking place on account of growing population and diversification of economic activity. Central Government has formulated a National Land Use Policy Outline (NLPO) and recommended to the States for implementation; this policy Outline envisages re-structuring of urban policy to ensure that highly productive land is not taken away for urban use.

Production and Distribution of Seeds in North Eastern States

2826. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have evolved any scheme for seed production and its distribution in the North Eastern parts of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have included the state of Bihar in the scheme; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) Seed Production and distribution is the responsibility of state Governments under their State Programmes. However, to supplement their efforts in this regard, there are Central Sector/Centrally